

प्राधिकार स प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 20]

नर्प विल्ली, शनिबार, मई 15, 1965 (बैसाख 25, 1887)

No. 20]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 15, 1965 (VAISAKHA 25, 1887)

इस भाग में मिश्र पूछ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नोटिस

NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 15 मई 1965 तक प्रकाशित किए गए ये:-

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 15th May 1965:-

अंक	No.)	संख्या और तारीख	द्वारा जारी किया गया	विषय
(Issue		(No. and Date)	(Issued by)	(Subject)
47	No. 2	9-ITC(PN)/65, dt. 26th April, 1965	Ministry of Commerce	Import of In-edible tallow from U. S. A. under the Agricultural Commodities Agreement signed on 31st Dec., 1964, between the Govt. of the United States of America and the Govt. of India under Title I of the U. S. Agricultural Trade Development and Assistance Act, as amended (P. L. 480)—Purchase Authorisation No. 39-145 and 39-145-OT both dt. the 18th March/1965.

ऊपर सिखे असाधारण राजपत्नों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्न भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्न प्रबन्धक के पास इन राजपत्नों के जारी होने की तारीख़ से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची CONTENTS

	des		पुष्ठ
	Pages		Pages
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर)		भाग I—श्वंड 3—रक्षा मंत्रालयद्वारा जारी की गई	
भारत सरकार के मंद्रालयों तथा उच्चतम		विधीतर नियमों, विनियमों, आदेशों और	
म्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों,		संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	18
विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से		भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा आरी की गई	
संबंधित अधिसूचनाएं	267	अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों	
भाग 1-खड 2(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत		आदि से संबंधित अधिसूचनाएं	239
सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय		भाग II—खंड 1अधिनियम, अध्यावेश और	
द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की		विनियम	
नियुक्तियों, पदोक्षतियों, छुट्टियों आदि से		भाग IIखंड 2विद्येयक और विद्ययकों संबंधी	
संबंधित अधिसूचनाएं	373	प्रवर समितियों की रिपोर्टे	~~

	पृष्ठ Pages		पृष्ठ Pages
माग II— खंड 3—उप-खंड (i)—-(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के संत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर)		भाग III— खंड 2—एकस्य कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें	169
केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार		भाग III - खंड 3 मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	35
के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय	757	भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाए जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें ग्रामिल हैं	2391
को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत		भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें	103
बनाये और जारी किये गये आदेश और अधि- सूचनाएं	1683	सस्याओं के विज्ञापन तथा नाइस पूरक सं० 20—	103
भाग II—खंड 4—-रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	137	8 मई, 1965 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट	653
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन		17 अप्रैल, 1965 को समाप्त होने वाले सप्ताह्व के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी	
कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	327	नीमारियों से हुई मृत्यु से संबंधित आंकड़े	665
PART I—Section 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations and Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	267	PART II—SECTION 3.—Sub-Section (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Min- istries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Cen- tral Authorities (other than the Adminis- trations of Union Territories)	1683
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	373	PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Rallway Administration, High Courts and the Attached and Sub-	137
PART I—Section 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations; Orders and Resolutions, issued by the Ministry of Defence	19	ordinate Offices of the Government of India	327 169
PART I—Section 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc.,	17	PART III—Section 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	35
of Officers issued by the Ministry of Defence	239	PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2391
Regulations	Wings No.	PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	103
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills		SUPPLEMENT No. 20—	
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including orders, byolaws, etc. of a general character) issued by		Weekly Epidemiological Reports for week-ending 8th May 1965	653
the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Contral Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	757	with a population of 30,000 and over in India during week-ending 17th April 1965	665

सदस्य

"

"

भाग I-खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चत्तम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर निथमों, विनियमों तथा आवेशों और संकल्पों से संबंधित धिधसुचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

"

षोजना आषोग

संकल्प

आयुर्वेद तथा अन्य चिकित्सा प्रणालियों पर पैनल नई दिल्ली, दिनांक 4 भई 1965

सं० स्वास्थ्य/6(11)/64—संकल्प स० स्वास्थ्य/1(23)/59 दिनांक 10 जून 1960 में आयुर्वेद पर गठित पैनल का अधिक्रमण करते हुये, योजना अयोग ने 'आयुर्वेद तथा अन्य चिकित्सा प्रणालियों पर पैनल' का गठन किया है। पैनल आयुर्वेद, यूनानी, अन्य चिकित्सा प्रणालियों, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि के क्षेत्र में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेगी और चौथी योजना के सम्बन्ध में भावी कार्यक्रम के बारे में योजना आयोग को सलाह देगा। पैनल निम्न प्रकार से होगा:—

- प्रो० एम० एस० थैकर, अध्यक्ष सदस्य, योजना आयोग, नई दिल्ली ।
- श्री मोहन लाल पी० श्यास, स्वास्थ्य मंत्री, उपाध्यक्ष गुजरात सरकार, अहमदाबाद ।
- 3. श्री भीखाभाई, आयुर्वेद मंत्री, सदस्य राजस्थान सरकार, जयपुर।
- श्री अनन्त निपाठी शर्मा, आयुर्वेद चक्रवर्ती, एम० ए०, शिरोमणि प्रेस, बरहामपुर, गंजाम, उड़ीसा।
- पंडित हरिदल शास्त्री,
 आयुर्वेदाचार्य,
 94-बी, दादर मेन रोड, बम्बई-14।
- आर्य वैद्यम् श्री पी० के० वारियर, आर्य वैद्यमाला, कोट्टाकल, दक्षिण मालवार।
- 7. कविराज डा॰ प्रभाकर चटर्जी, एम॰ ए०, 172, बोबाजार स्ट्रीट, कलकत्ता-12।
- आयुर्वेद शिरोमणि श्री गुलराज शर्मा,
 मिश्र, आयुर्वेदाचार्य,
 नई शक्र्याड़ी, नागपुर ।
- आचार्य बद्री विशाल विपाठी,
 74/71, कानपुर (उ० प्र०)।
- आयुर्वेद शिरोमणि श्री एन० एच० जोशी, "सामर्थ कृपा" प्लाजा सिनेमा के पीछे, दादर, बस्बई।
- 11. पंडित राम नारायण शर्मा, आयुर्वेदाचार्य, "रस निकेतन", जवाहर मार्ग, इन्दौर शहर, मध्य प्रदेश।
- 12. डा॰ सी॰ द्वारकानाथ, सलाहकार (देशी औषध प्रणाली) स्वास्थ्य मंत्रालय, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली।

- 13. हकीम अब्दुल हामीद, मृताधली, निदेशक, ृंहमदर्द दवाखाना (वक्फ), लालकुआं, दिल्ली ।
- 14. डा० आई० एच० अन्सारी, एम०बी०बी०एस०, प्रधानाचार्य, तिबिया कालेज, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश ।
- 15. डा॰ के॰ जी॰ सक्सेना, होम्योपैथी के अवैतनिक सलाहकार, स्वास्थ्य मंत्रालय, पिटयाला हाउस, नई दिल्ली।
- 16. डा॰ जे॰ एन॰ मजुमदार, 852, ब्लाक पी॰, न्यू अलीपुर ृंकलकत्ता-53 ।
- 17. डा॰ जे॰ एम॰ जुखावाला, प्राकृतिक चिकित्सा क्लोनिक, सुनामा हाउस, तीसरी मंजिल, 140, कुम्बाला हिल, बम्बई-26।
- 18. डा॰ आर॰ जी॰ कृष्णाक्षे, बी॰एस॰सी॰एच॰-टी॰, प्राकृतिक चिकित्सा, परामर्शदाता, शरदा-ए रोड चर्च गेट, बम्बई-1।
- 19. पं० शिव शर्मा, सदस्य-सचिव आयुर्वेद सलाहकार, योजना आयोग, नई दिल्ली ।
- 2. पैनल विशेष समस्याओं के अध्ययन के लिए उपसमितियां गठित कर सकता है और सदस्यों को सहयोजित कर सकता है।
- पैतल की बैठकें आवश्यकतानुसार नई दिल्ली या अन्य स्थानों पर समय-समय पर होंगी।

आवृश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के राजपन्न में प्रकाशित कर दी जाय और सब सम्बन्धित व्यक्तियों को भेज दी जाय।

> के० ए० पी० स्टीवेन्सन, संयुक्त सचिव

साम्याचिक विकास और सहकारिता मंत्रासय

संकरूप

नई दिल्ली, दिनांक 3 मई 1965

सं० 14/5/65-पी०आर०—इस मंद्रालय के 12 मई 1964 के संकल्प सं० 14/3/64-पी०आर० के कम में, परिषद् के सदस्यों की सूची में निम्न नाम जोड़े जाते हैं:—

- (1) डा० बी० के० आर०वी० राव०, सदस्य (कृषि), योजना आयोग।
- (2) श्री देवकी नन्दन नारायण, संसद-सदस्य।
- (3) श्री के॰ जी॰ लिमये, अध्यक्ष, कोलाबा, जिला परिषष्, डाकघर अलीबाग (जि॰ कोलाबा), महाराष्ट्र ।

- (4) श्री प्रभाकर अंकोलेकर अध्यक्ष, नगर पंचायत, सिडला-पुर, नार्थ कनारा जिला, मैसूर ।
- (5) श्री आर० एस० रंधावा, आयुक्त, कृषि उत्पादन, पंजाब, और
- (6) श्री अञ्चासाहिब सहस्रबुद्धे, अध्यक्ष, ग्राम औद्योगीकरण समिति, योजना आयोग ।

आपुरा

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्न में आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।

एन० ई० एस० राघवचारी, अतिरिक्त समिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-11, दिनांक 3 मई 1965

सं० 1/2/65-ए० एन० एल०—राष्ट्रपति जी अन्डमान और निकोबार द्वीपों के संघ राज्य क्षेत्र से सम्बन्धित गृह मंत्री की सलाहकार समिति के लिए निम्नलिखित गैर-सरकारी सदस्यों, को 31 मार्च 1966 को ममाप्त होने वाले वर्ष के लिये महर्ष मनोनीत करते हैं:—

- 1. श्री अतुल चन्द्र ह्वलदार
- 2. श्री दुर्गा प्रसाद
- 3. श्री के० अरविन्दाक्षन्
- 4. कच्छाल द्वीप की रानी छांगा
- 5. श्री मनोरंजन भक्त
- 6. श्री फेड

अ० द० पाण्डे, संयुक्त सम्बद

लाका और कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 1965

सं० 6-5/64-अर्थ नीति—इस मन्त्रालय ने भारत सरकार के प्रस्ताव सं० 6-5/64-सी०(ई) दिनांक 25 सितम्बर, 1964 में नीचे लिखे हुए संशोधन सामान्य सूचना के लिये अधिसूजित किए हैं:—

- रेवेरेन्ड मैथ्यू कोटैया, पीएच० डी०, कोटैया हाउस, वेन्नाला पोस्ट आफिस, एडापल्ली दक्षिण, केरल अभी से अर्थ-णास्त्रियों के पैनल के सदस्य होंगे।
- 2. कम-संख्या 1 में प्रोफेसर एम० एल० दन्तवाला के नाम के बाद आनेवाले शब्द "अर्थ शास्त्र विभाग, बम्बई विश्व-विद्यालय, बम्बई" के स्थान पर "अध्यक्ष, कृषि मूल्य आयोग, खाद्य और कृषि मन्त्रालय, नई दिल्ली" शब्द लगार्ये।
- 3. कम संख्या 3 में डा॰ राज कृष्ण के नाम के बाद आने वाले णब्द, "इंस्टीट्यूट ऑफ एकोनोमिक ग्रोथ, दिल्ली" के स्थान पर "सदस्य, कृषि मूल्य आयोग, खाद्य और कृषि मन्त्रालय, नई दिल्ली" शब्द लगायें।

अतर चन्द जैन, अवर सचिव

(भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषदः)

नई दिल्ली, दिनांक 5 मई 1965

मं ०-1-80/64-कॉम० 1--भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति के उप-नियमों के उपनियम XII की धारा (4) के अनुसार केन्द्रीय सरकार उपरोक्त समिति के 31 मार्च, 1964 को समाप्त होने बाले वर्ष के निम्नलिखित आय और व्यय के लेखे और उन पर महालेखाकार, केरल की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट मुद्दित करती हैं:-

सन् 1963-64 की आय और व्यय का लेखा

भाग 1सामान्य काय								
आय		च्यय						
विवरण	राशि	विवरण	राशि					
	₹0		र ०					
आरम्भिक शेष (ओपनिंग बैर्लेस)	2,46,048		,					
(क) भारत सरकार से प्राप्त रकम	8,00,000	(क) समिति का प्रशासन	1,36,050					
(ख) समिति द्वारा प्राप्त अन्य रकम .	90,394	(ख) सुपारी की खेती में सुधार सम्बन्धी किए गए कार्ये	5,71,491					
(ग) पूर्वकथित रकम के निवेश द्वारा प्राप्त रकम		(ग) भारत में सुपारी के सुधार और विकास तथा इसके उत्पादन के सम्बन्ध में किए गए कार्य.	1,500					
(ष) विविध (पुनर्गृहीत पेशगी तथा जमा)	2,01,671	(घ) सुपारी के विषणन में सुधार करने के विषय में किये गए कार्य.	43,353					
		(ङ) विविध (पुनर्गृं हीतीय पेशगी और जमा)	1,78,224					
		कुल ठ ्यय .	9,30,618					
		इतिगोष (क्लोजिंग बैलेंस) .	4,07,495					
महायोग :	13,38,113	महायोग : .	13,38,113					

	भाग	II-—तीसरी पंचर	तर्वीय योजना की योजनाएं	
घिव	विवरण		विवरण	राणि रु०
आरस्भिक शेष (क) भारत सरकार से प्राप्त रकम		70 2,40,130	मुपारी की खे ती करने के विषय में किये गये कार्य	2,23,386
1963-64 के लिए अनुदान वापिस की गई रकम निकाल कर	2,40,200	2,70,100	कुल व्यय : इतिगोष :	2,23,386 16,814
योग :	2,40,130	2,40,200	महायोग :	2,40,200
	वी० आर रतीय केन्द्रीय स्	० श्रीनिवासन अधीक्षक		े टी० पोलस सचिव

प्रमाणपत्र

समस्त सूचना आदि जिसकी मुझे आवश्यकता पड़ी, प्राप्त करके मैने भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति कोजीकोडा, के उपर्युक्त लेखों की जांच की और संलग्न लेखा जांच रिपोर्ट में व्यक्त विचारों को व्यान में रखते हुए, मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरे विचार से ये लेखें विधिवत रूप से रखे गये हैं और समिति की गतिविधियों का सत्य रूप प्रविशित करते हैं। मेरा यह वक्तव्य समिति की लेखा पुस्तकों और मुझे दी गई सूचना आदि पर आधारित हैं।

> टी० एन० कुरियाकॉस महालेखाकार, केरल 20-1-65

भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति के खातों की ऑडिट रिपोर्ट, 1963-64

भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति रिजस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज ऐक्ट (1860 का XXI) के अस्तर्गत एक सोसायटी के रूप में रिजस्टर्ड की गई है। समिति की आय का मुख्य स्रोत भारत सरकार से प्राप्त राशि है जो कि सहायक अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। समिति ने 1963-64 वर्ष के लिए भारत सरकार से 10 लाख रुपया सहायक अनुदान के रूप में प्राप्त किया।

2. विसीय परिणाम

(क) पिछले चार वर्षों में समिति की आय और व्यय का सारांश नीचे दिया जाता है जो कि मुख्य शीर्षों में धर्गीकृत किया गया है :—

प्राय					(लाख रुपर	रों में)	
				1960-61	1961-62	1962-63	1963-64
1.	भारत सरकार से प्राप्त अनुदान		•	18.73	10.06	10.66	10.4
	नरसरीज, अनुसंधान केन्द्रों आदि से अन्य प्राप्तियां			0.69	0.42	0.75	0.90
	पेशगियों की जमा और वसूली	•	٠	2.18	2.20	1.83	2.0
	योग		•	21.60	12.68	13.24	13,3
यय							
	प्रशासन	•	•	1.15	1.27	1.27	1.3
2.	सुपारी की खेती में सुधार			16.97	7.00	9.09	7.9
3.	सुपारी और इससे बने पदार्थों का विकास और सुधार			0.76	0.59	0.27	0,0
	सुपारी और इससे बने पदार्थों का विकास और सुधार			0.66	0.69	0.28	0.4
5.	विविध (वसूली करने योग्य पेशगियों का भुगतान	और					
	जमा)	•	•	2.39	1.86	1.88	1.7
	मोग			21.93	11.41	12.79	11.5

आलोच्य वर्ष में सुपारी की खेती में सुधार करने के लिए तथा सुपारी और सुपारी से बने पदार्थों के विकास और सुधार तथा उनके विपणन के लिए जो उपाय किये गये उन पर 8.40 लाख रुपया खर्च किया गया जो कि इस वर्ष के लिए समिति के कुल खर्च का 73 प्रतिशत होता है। इसमें से 5.24 लाख रुपया समिति ने सीधा अपनी योजनाओं पर खर्च किया। 2.88 लाख रुपया 7 राज्य सरकारों को सहायक अनुदान के रूप में दिया गया और 0.28 लाख रुपया उन अन्य निकायों और संस्थानों को विया गया जो कि सुपारी की खेती, सुपारी सुखाने (क्योरिंग) तैयार करने (प्रोसेसिंग), श्रेणीकरण करने, विपणन और सुपारी तथा सुपारी से बने पदार्थों का निर्माण करने के कार्य में लगी हैं।

3. पौदों की हानि

मुपारी की खेती में सुधार करने के लिए जो उपाय किये गये उनमें समिति द्वारा घलाये जा रहे सुपारी अनुसंधान केन्द्रों द्वारा क्वालिटी पौदों का वितरण भी सम्मिलित है। प्रादेशिक सुपारी अनुसंधान केन्द्र, मोहितनगर, जिसने अनुसंधान का कार्य 1961-62 में प्रारम्भ किया, में 1961-62 से अप्रैल, 1963 तक की अविध में जो भारी क्षति हुई, उसके परिणामस्वरूम 18,208 रूपये मूल्य की 1,40,065 पौदों का नुक्सान हुआ। सितम्बर,1964 में समिति ने रिपोर्ट दी है कि मौसम की खराबी, भूमि की अविकसित अवस्था, सियाई सुविधाओं की कमी और "खांस" वास के उगने के कारण यह हानि हुई।

4. अनुदानों का उपयोग

समिति द्वारा दी गई अनुदानों का उचित उपयोग किया जा रहा, इसकी निगरानी समिति (1) राज्य सरकारों द्वारा आयोजित योजनाओं के सम्बन्ध में महालेखाकार से ऑडिट सर्टिफिकेट और (2) अन्य मामलों में उपयोग सर्टिफिकेट, प्राप्त करके रखती है। नवम्बर, 1964 के अन्त में, 1956-57 से 1963-64 तक दी गई सहायक अनुदान के 42 मामलों में, 4.54 लाख रुपये की कुल राशि के सम्बन्ध में ऑडिट और उपयोग सर्टिफिकेट प्राप्त होने बाकी थे।

(ह०) टी० एन० कुरियाकॉस महालेखाकार, केरल जे० एस० उप्पक्त, अवर सचिव

रिक्षा मंत्राहरू

नई दिल्ली, दिनांक मई 1965

सं० एफ० 7-36/65-टी० 1—26 अप्रैल, 1964 से धनवाद स्थित भारतीय खनन स्कूल की शासी-परिषद् के पुनर्गठन के सम्बन्ध में शिक्षा मंद्रालय की अधिसूचना संख्या एफ० 7-17/64-टी० 1, तारीख 22 अगस्त, 1964 का सन्दर्भ । उपर्युक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 1 'अध्यक्ष' के नीचे एतद् द्वारा निम्नलिखित परिवर्तन किया जाता है :—

"सचिव (शिक्षा), शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली" के स्थान पर "श्री जी० के० चन्दीरमानी, शिक्षा सलाहकार (तकनीकी) और पदेन अतिरिक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली" रखा जाए।

> जी॰ एन॰ वासवानी, सहायक शिक्षा सलाहकार (तक॰)

सिंचाई व विजली मंत्रालय

संकरप

नई दिल्ली, दिनांक 4 मई 1965

सं० 1/3/62-नीति अनुभाग--इस मंत्रालय के संकल्प सं० 1/3/62-नीति, तिथि 18 मई 1964 के दूसरे पैरे में निम्नलिखित संशोधन किया जाये।

फ्रम के स्थान पढ़िये सं०

4 श्री बी० सी० गंगोपाध्याय, श्री ए० दास, उप सचिव, उप सचिव, सिंचाई व बिजली सिंचाई व बिजली मंत्रालय, मंत्रालय, नई दिल्ली। नई दिल्ली।

आपेश

आवेश विया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि समिति में प्रतिनिधित्व प्राप्त सभी मंत्रालयों / राज्य सरकारों/संगठनों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को साधारण सूचना के लिये भारत के राजपत्न में प्रकाशित कर दिया जाये।

के० जी० सार० अय्यर, संयुक्त सचिव

निर्माण तथा आवास मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 5 मई 1965

सं 0 14(30)/64-ई 0 डब्लू, 1-भारत सरकार ने उस अविध को 31 मई, 1965 तक बढ़ा दिया है, जिसमें कि संकल्प सं 0 14 (30)/64-ई 0 डब्लू 1, तारीख 17 अगस्त 1964 के अनुसार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की प्रक्रिया और कार्य-प्रणाली के परीक्षण के लिए बनाई गई अध्ययन टोली (स्टडी टीम) को अपनी रिपोर्ट दे देने की संभावना थी।

आपुरा

 आदेश दिया गया कि इस संकल्प की प्रतिलिपि सभी संबं-धित व्यक्तियों को भेज दी जाये और सामान्य सूचना के लिए इसे भारत के राजपक्ष में प्रकाशित करा दिया जाये।

रामचन्द मेहरा, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

संकरूप

नई दिल्ली, दिनांक 26 अप्रैल 1965

सं० वे० बो०-12 (1)/64—भारत सरकार ने अपने संकल्प संख्या वे० बो-12(1)/64, तारीख 5 अप्रैल 1965 के द्वारा भारी रसायन और उर्वरक उद्योगों के लिए एक केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड स्थापित किया था। उपर्युक्त संकल्प में निर्दिष्ट सदस्यों के अलावा निम्नलिखित व्यक्तियों को एतद् द्वारा मजदूरी बोर्ड के सदस्य नियुक्त किया जाना है:—

मालि**कों के प्रतिनिधि** स<mark>वस्य</mark> श्री डी० एम० क्रिवेदी

इंडियन कैमिकल मैंन्यु-फैक्चरेंस एसोसियेशन, बम्बई का नामित व्यक्ति।

कामगरों के प्रतिनिधि सदस्य श्री वी० वी० डाविड

श्री जी० सुन्दरम

राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का नामित व्यक्ति । अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का नामित व्यक्ति ।

आवेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्न में आम सुचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

बी॰ आर॰ सेठ, उप-सचिव

संकरप

नई दिल्ली, दिनांक 27 अप्रैल 1965

सं० डब्लयू०बी०-21(13)/65-मुख्य पत्तनों के पत्तन और गोदी कामगरों के केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड ने, जिसकी नियुक्ति भारत सरकार ने अपने संकल्प संख्या डब्लयू० बी०-21(4)/64, तारीख 13 नवम्बर 1964 द्वारा की थी, अंतरिम सहायता की मंजूरी के लिए सिफारिशें कर दी हैं, जोकि परिशिष्ट में दी गई हैं।

 सरकार ने मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार करने और सम्बन्धित नियोजकों से उन्हें यथाशीघ्र लागू करने के लिए अनुरोध करने का निश्चय कर लिया है।

भार र

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्न में प्रकाशित किया जाए।

पी० एम० मेनन, समिव

परिशिष्ट

मुख्य पत्तनों के पत्तन और गोबी कामगरों का केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड

भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंद्रालय ने अपने संकल्य सं० ढब्ल्यू० बी०-21(4)/64, तारीख 13 नवम्बर 1964 द्वारा मुख्य पत्तनों पर काम करने वाले पत्तन और गोदी कामगरों के लिए एक केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड गठित किया था। उक्त संकल्प पैरा 3 के खण्ड (घ) द्वारा बोर्ड से मजदूरों की अंतरिम सहायता सम्बन्धी मांगों के बारे में सिफारिणों काम णुरू करने की तारीख से तीन माह के अन्दर भेजने को कहा था। संबंधित पक्षों को सुनने के बाद बोर्ड ने 12 से 14 मार्च 1965 तक विचार-विमर्ण किया, परन्तु बोर्ड इस बैठक में अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। चूंकि तीन माह की अवधि 14 मार्च 1965 को समाप्त हो रही थी, अतः बोर्ड ने अपने प्रस्ताव तारीख 14 मार्च 1965 द्वारा सरकार से प्रार्थना की कि अंतरिम सहायता सम्बन्धी सिफारिणों भेजने के लिए निश्चित समयाविध को एक माह द्वारा बढ़ा दिया जाए।

अंतरिम सहायता के प्रश्न पर विश्वार करने के लिए बोर्ड की दुबारा बैठक 7, 8 और 9 अप्रैल, 1965 को हुई। बोर्ड इस सम्बन्ध में सभी मामलों पर सम्यक विचार करने के बाद निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंचा है:

I—मजदूरी बोर्ड की सिफारिशें, जोकि आगे दी गई हैं, मुख्य पत्तनों पर पत्तन और गोदी काम से संबंधित कर्मचारियों के निम्निलिखित वर्गों पर लागू होनी चाहिएं अर्थात्—

(क) मुख्य पत्तन प्राधिरणों के कर्मचारी

- (1) मुख्य पत्तनों के कर्मचारियों की श्रेणी III और IV वर्गीकरण सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट के अन्तर्गत आने वाले बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, कोडला, मद्रास, विशाखापत्तनम के मुख्य पत्तनों के प्राधि-करणों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के सभी वर्ग और मार्मागोवा पत्तन के समान वर्ग।
- (2) श्रमिक, क्लर्क, पर्यवेक्षक आदि कर्मचारियों के और कोई वर्ग जो किसी मुख्य पत्तन प्राधिकरण द्वारा पहले या बाद में बनाए गए पदों पर काम करते हों और जो वर्ग I और वर्ग II अधिकारी नहीं माने जाते।
- (3) 'ए', 'बी', 'सी' वर्गी को मिलाकर मुख्य पत्तन प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त सभी वर्गी के तट कर्मचारी और सीधे पत्तन प्राधिकरणों द्वारा वैनिक या अन्य रूप से नियुक्त अन्य सभी कर्मचारी।

(ख) गोबी कामगर (रोजगार का विनियमन) अधिनियम 1948, द्वारा परिभाषित गोबी कामगर।

- (1) बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कोचीन और विशाखापत्तनम के मुख्य पत्तनों सम्बन्धी गोदी कामगर (रोजगार का विनियमन) योजना की अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारी ।
- (2) बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के पत्तनों पर अपंजीकृत गांदी कामगर (रोजगार का विनियमग) योजना के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारी ।
- (3) कर्मचारियों के व वर्ग जोकि कांडला और मार्मागोवा पत्तनों पर मह 1 के अन्तर्गत आते हैं।
- (4) कर्मचारियों के वे वर्ग जोिक कोचीन, विशाखापत्तनम, कांडला और मार्मागोवा के पत्तनों पर मद् 2 के अन्तर्गत आते हैं।
- (5) कर्मचारियों के वे वर्ग जोकि सभी मुख्य पत्तनों पर मद्द 1 और 2 में आते हैं, चाहे उन पर योजनाएं लागू हों या न।

- (ग) गोदी मजदूर बोडों और उनके प्रशासनिक निकामों द्वारा नियुक्त कर्मचारी ।
- (घ) सूचीबद्ध नियोजकों द्वारा नियुक्त कर्मचारी ।
- (ड) पत्तन प्राधिकरणों, गोदी मजदूर बोर्डी, प्रशासनिक निकायों, सूचीबद्ध नियोजकों और पंजीकृत नियोजकों के अलावा अन्य नियोजकों के कर्मचारी।
 - (1) खत्ता और डिपुओं पर नियुक्त और (अयस्क) कर्मचारी ।
 - (2) मालगोदामों और पारगमन शेडों में माल के प्रबन्ध के लिए नियुक्त कर्मचारी।
 - (3) पूर्णतः डाकसैंड स्ट्रीम पर नियुक्त नावों, माल बोटों और बंजरों के कर्मचारी जिसके काम का सम्बन्ध नावों को भरने और खाली करने तथा गोदी और पत्तन काम की अन्य प्रक्रियाओं से है।
 - (4) गोदी क्षेत्रों में नदी जलयानों, जहाजों, नावों, ट्रकों आदि से सभी प्रकार का माल (चाय की पेटियां मिला कर) लादने और उतारने में नियुक्त कर्मचारी।
 - (5) वे कर्मचारी जो गोदी कामगर (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत "गोदी कामगर" की परिभाषा में आते हैं।

II— खण्ड I में निर्विष्ट कर्मचारियों के सभी वर्गों को, जिन्हें महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर से मिल रहा है, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बराबर महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए। जब सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों में सुधार करे, तब इन कामगरों को भी महंगाई भत्ता बढ़ी हुई दरों पर दिया जाना चाहिए। बोर्ड की अंतिम सिफारिशें लागू होने तक इस पद्धति को अपनाना चाहिए।

III-—(क) यदि कर्मचारियों के किसी वर्ग को महंगाई भत्ता सरकारी दरों से नहीं दिया जा रहा है तो ऐसे वर्गों को भी 1-10-1964 से निम्नलिखित दरों पर महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए :—

	महंगाई भत्ता				
					₹०
110 ₹∘	से कम				7.50
110 ₹∘	ओर अधिक	परन्तु 1	50 रु० से	कम.	16.50
150 ₹∘	और अधिक	परन्तु 2	10 रु० से	कम.	12.00
210 ₹∘	से 300 तक		•		16.00
301					17.00
302			•		18.00
303			•		19.00
304					20.00
305					21.00
306	•			-	22.00
307	-			•	23.00
308	•		•	•	24.00
309					25.00
310					26.00
311			-		27.00
312			-		28.00
314	•		•	•	30.00
315					31.00

	वेतन सीमा			महंगाई भत्ता		
					र्०	
316 से 384					31.00	
385		٠		•	31.00	
386	-		•		32.00	
387					33.00	
388			•		34.00	
389		•			35.00	
390					36.00	
391					37.00	
392					38.00	
393			i.		39.00	
394			•		40.00	
39 5					41.00	
396					42.00	
397		•			43.00	
398					44.00	
399		•			45.00	
400 से 580					50.00	
581					51.00	
582	-				52.00	
58 3					53.00	
584		•			54.00	
585					55.00	
586					56.00	
587		•			57.00	
588					58.00	
589	•				59.00	
590		•			60.00	
591					61.00	
592					62.00	
593			-	1	63.00	
594				,	64.00	
595					65.00	
596					66.00	
597	•				67.00	
598	•				68.00	
599					69.00	

बशर्ते कि:---

यदि महंगाई भर्से की कोई भिन्न योजना किन्हीं कर्मचारियों पर लागू होती है और यदि उस योजना के अन्तर्गत उन कर्म-चारियों ने 31-1-1964 से महंगाई भर्ते में यूद्धि उपर्युक्त वृद्धि से कम प्राप्त न की हो तो इन कर्मचारियों के महंगाई

PLANNING COMMISSION

RESOLUTION

Panel on Ayurveda and other systems of Medicine New Delhi, the 4th May 1965

No. HLH/6(11)/64.—The Planning Commission has constituted a 'Panel on Ayurveda and other Systems of Medicine' in supersession of the Panel on Ayurveda which was set up under Resolution No. HLH/1(23)/59, dated the 10th June, 1960. The Panel will review the progress of Plans in the field of Ayurveda, Unani, Other Systems of Medicine, Homoeopathy, Nature Cure etc. and advise the Planning Commission on future programmes relating to the Fourth Five Year Plan. The Panel will consist of the following:

Chairman

1. Prof. M. S. Thacker, Member,
Planning Commission, New Delhi.

भसे में कोई और वृद्धि नहीं। की जाएगी। यदि ऐसा न हो तो ऊपर खण्ड (क) में दी गई वरों तथा उन कर्मशारियों द्वारा प्राप्त बढ़ी वरों के अन्तर के समान दरों से उन्हें महंगाई भसे में 1-10-1964 से वृद्धि दी जानी चाहिए।

समेकित मजूरी पाने वाले कर्मंचारियों व उजरती दरों के कामगरों को 1-10-1964 से 7.50 रु० प्रति मास न्यूमतम महंगाई भला दिया जाना चाहिए। खण्ड (क) के अन्तर्गत दिये जाने वाले महंगाई भले की राणि निर्धारित करते समय एक ही तरककी सरणि के अधिक और कम वेतन पाने वाले कामगरों की मजदूरी के अन्तर, यदि कोई हो, की गणना की जानी चाहिए।

- (ख) जब कभी केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भसे की दरों में उपबन्ध (i) में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के आधार पर वृद्धि करे तब उपर्युक्त उपबन्ध (i) और (ii) में निर्दिष्ट कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि की जानी चाहिए।
- (IV) उपर्युक्त अदायिगयों के अलावा खण्ड (i) में निर्दिष्ट कर्मचारियों के सभी वर्गों को 1-2-1965 से 7.80 रु० प्रति मास की अंतरिम सहायता दी जानी चाहिए।
- (V) अमानी या उजरती दर पर काम करने वाले दिहाड़ी के मज़दूरों की अंतरिम सहायता की दैनिक दर वर्तमान प्रथानुसार उपर्युक्त मासिक राशि का 1/26 या 1/30 हिस्सा होनी चाहिए। जहां इस प्रकार की कोई प्रथा न हो वहां यदि किसी कामगर को सप्ताह की छुट्टी के दिन की कोई मजदूरी नहीं दी जाती तो उसे अंतरिम सहायता की दैनिक दर उपर्युक्त मासिक राशि का 1/26 होगी।
- (VI) बोर्ड की अंतिम सिफारिशें लागू होने तक खण्ड IV में निर्विष्ट अंतरिम सहायता को एक अलग मद्द के रूप में (न मूल मजदूरी का हिस्सा और नहीं महंगाई भत्ता का हिस्सा) दिखाया जाना चाहिए। परन्तु इस अंतरिम सहायता को कुल मजदूरी का हिस्सा उसी प्रकार माना जायगा जिस प्रकार दास आयोग द्वारा मंजूर किया गया विधित महंगाई भत्ता माना जाता है।

ह० एस० वी० दवे

ह० बंसी लाल

ह० डी० टी० लकड़ावाला

ह० एस० आर० कुलकर्णी

ह० आई० बी० दास गुप्ता

ह० माखन चैटर्जी

ह० टी० के० परमेश्वरननांबियार

ह० मैक्षीय बोस

ह० एस० सी० सेठ

ह० एन० अहमद

9-4-1965

Vice-Chairman

 Shri Mohanlal P. Vyas, Health Minister, Government of Gujarat, Ahmedabad.

Members

- Shri Bheekha Bhai, Minister for Ayurveda, Government of Rajasthan, Jaipur.
- Sri Ananta Tripathi Sarma, Ayurveda Chakravarty, M.A., Siromani Press, Berhampur, Ganjam, Orissa.
- Pandit Hari Datta Shastri, Ayurvedacharya, 94-B, Dadar Main Road, Bombay-14.

- Arya Vaidyam Shri P. K. Warrier, Arya Vaidya Sala, Kottakal, South Malabar.
- Kaviraj Dr. Prabhakar Chatterjee, M.A., 172, Bowbazar Street, Calcutta-12.
- 8 Ayurveda Shiromani Shri Gulraj Sharma, Mishra, Ayurvedacharya, New Shakurawari, Nagpur.
- 9. Acharya Badri Vishal Tripathi, 74/71, Kanpur, U.P.
- Ayurveda Shiromani Shri N. H. Joshi, "Samartha Kripa", behind Plaza Cinema, Dadar, Bombay.
- Pandit Ram Narain Sharma, Ayurvedacharya. "Ras Niketan", Jawahar Marg, Indore City, Madhya Pradesh.
- Dr. C. Dwarkanath, Adviser (Indigenous Systems of Medicine), Ministry of Health, Patiala House, New Delhi.
- Hakim Abdul Hameed, Mutawalli, Director, Hamdard Dwakhana (Wakf), Lal Kuan, Delhi.
- Dr. I. H. Ansari, M.B.B.S., Principal, Tibbia College, Aligarh, U.P.
- Dr. K. G. Saxena, Hony. Adviser in Homoeopathy, Ministry of Health, Patiala House, New Delhi.
- Dr. J. N. Majumdar, 852, Block P. New Alipore, Calcutta-53.
- Dr. J. M. Jussalwalla, Natural Therapy Clinic, Sunama House, 3rd Floor, 140, Cumballa Hill, Bombay-26.
- Dr. R. G. Krishnatray, B.Sc., M.D., Consulting Naturopath, Sharda—A Road, Churchgate, Bombay-1.

Member-Convener

- Pt. Shiv Sharma, Adviser on Ayurveda, Planning Commission, New Delhi.
- 2. The Panel may constitute Sub-Committees and coopt members for studies of special problems.
- 3. The Panel or its Committees may meet as often as may be necessary at New Delhi or any other place.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India and communicated to all concerned,

K. A. P. STEVENSON, Jt. Secy.

MINISTRY OF COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Community Development)

RESOLUTION

New Delhi, the 3rd May 1965

No. 14/5/65-PR.—In continuation of this Ministry's Resolution No. 14/3/64-PR, dated May 12, 1964, the following names are added to the list of members of the Council:

- 1. Dr. V. K. R. V. Rao, Member (Agriculture), Planning Commission.
- 2. Shri Devki Nandan Narayan, M.P.
- Shri K. G. Limaye, President, Kolaba Zila Parishad, P.O. Alibagh (Dist. Kolaba), Maharashtra.
- 4. Shri Prabhakar Ankolekar, Chairman, Town Panchayat, Sidlapur, North Kanara district, Mysore.
- Shri R. S. Randhawa, Commissioner for Agricultura! Production, Punjab, and
- 6 Shri Annasaheb Sahasrabudhe, Chairman, Rura Industrialization Committee, Planning Commission.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. E. S. RAGHAVACHARI, Addl. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-11, the 3rd May 1965

No. 1/2/65-ANL.—The President is pleased to nominate the following non-official members to the Advisory Committee in respect of the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands associated with the Home Minister, for the year ending 31st March 1966:—

- 1. Shri Atul Chandra Hawaldar.
- 2. Shri Durga Prasad.
- 3. Shri K. Aravindakshan.
- 4. Rani Chhanga of Katchall.
- 5. Shri Monoranjan Bhakta.
- 6. Shri Fred.

A. D. PANDE, Jt. Secv.

DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY

RESOLUTION

New Delhi, the 6th May 1965

No. 20(1)/64-Handicrafts.—The Government of India have decided to nominate Shrimati Kamala Reddy, a non-official, as member of the All India Handicrafts Board, as reconstituted, vide this Department's Resolution No. 20(1)/64-Handicrafts, dated the 28th December, 1964, with immediate effect.

2. The term of office of Shrimati Kamala Reddy will be the same as for other non-official members of the Board.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

P. SITARAMAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 4th May 1965

No. 15(21)TEX.(D)/62/TEX.(E).—The Government of India have decided to dissolve the Export Promotion Panel with effect from 4th January, 1965 as a separate Export Promotion Council for Woollen Textiles has since been formed.

A. G. V. SUBRAHMANIAM, Under Secy.

MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE (Department of Agriculture)

New Delhi, the 30th April 1965

No. 6-5/64-Econ. Py.—In the Resolution of the Government of India in this Ministry issued under No. 6-5/64-C(E) dated the 25th September 1964, the following changes are notified for general information:

- (1) Rev. Mathew Kottiah, Ph.D., Kottiath House, Vennala P.O., Edappally South, Kerala will also be a regular Member of the Panel of Economists with immediate effect.
- (2) Against S. No. I after the name of Professor M. L. Dantwala, for the words "Department of Economics, University of Bombay, Bombay", substitute the words "Chairman, Agricultural Prices Commission, Ministry of Food and Agriculture. New Delhi."
- (3) Against S. No. 3, after the name of Dr. Raj Krishna, for the words "Institute of Economic Growth, Delhi," substitute the words "Member, Agricultural Prices Commission, Ministry of Food & Agriculture, New Delhi."

A. C. JAIN, Under Secy,

Indian Council of Agricultural Research

New Delhi, the 5th May 1965

No. 1(80)/64-Com. I.—In pursuance of the provision of clause (4) of Bye-Law XII of the Bye-Laws of the Indian Central Arcanut Committee, the Central Government hereby publish the following accounts of the "Receipts" and "Expenditure" of the Committee and the Audit Report of the Accountant General, Kerala, thereon for the year ending 31st March, 1964:—

RECEIPTS AND EXPENDITURE STATEMENT FOR 1963-64—Part I—Normal Activities.

RECEIPTS	Expenditure				
Particulars	Amount	Particulars	Amount		
	Rs.		Rs.		
Opening Balance	2,46,048	(a) Administration of the Society	1,36,050		
(a) Money received from Government of India	8,00,000	(b) Measures taken in connection with work on			
(b) Other moneys received by the Society	90,394	improvement of arecanut cultivation	5,71,491		
		(c) Measures taken in connection with work on			
(c) Interest received from investment of such		the development and improvement of arecanut			
moneys as aforesaid	\rightarrow	and its production in India	1,500		
AD ARTHUR Many AND		(d) Measures taken in connection with improve-	42.252		
(d) Miscellaneous (Advances recovered and de-	0.01.671	ment in marketing of arecanut	43,353		
posit)	2,01,671	(e) Miscellaneous (Advance Recoverable and deposit)	1,78,224		
		Total Expenditure	9,30,618		
		Closing Balance	4,07,495		
GRAND TOTAL	13,38,113	Grand Total .,	13,38,113		
PART	IIThird Five	Year Plan Schemes.			
	Rs.		Rs.		
Opening Balance	70	Measures taken in connection with work on			
		improvement of arecanut cultivation	2,23,386		
(A) Money received from Govt. of India	2,40,130				
		Total expenditure	2,23, 386		
Grant for 1963-64 2.40.200		_			
Less refunds		Closing Balance	16,814		
		Crossing Darantoo 11 11 11 11 11	10,017		
2,40,130					
TOTAL	2,40,200	Total	2,40,200		

Sd/- 'V. R. SRINIVASAN
Superintendent
I.C.A.C.

Sd/- T.T. PAULOSE
Secretary
Indian Central Arecanut Committee

CERTIFICATE

I have examined the foregoing accounts of the Indian Central Arecanut Committee, Kozhikode and obtained all the information and explanations that I required and subject to the observations in the Audit Report appended, I certify, as a result of my audit that in my opinion these accounts are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Committee according to the best of my information, and explanations given to me and as shown by the books of the Committee.

Sd/- T. N. KURIAKOS Accountant General, Kerala ▶ | 截截 20-1-65,

Audit Report on the Accounts of the Indian Central Arecanut Committee for the Year 1963-64s

The Indian Central Arecanut Committee has been registered as a Society under the Registration of Societies Act (XXI of 1860). The main source of income of the Committee is the amount received by it as grant-in-aid from the Government of India. A sum of Rs. 10.40 lakhs was received by the Committee as grant-in-aid from Government of India for 1963-64.

2. Financial Results ;---

(a) A summary of the receipts and expenditure of the Committee for the last 4 years is given below classified under broad heads:

	Receipts				In lakh	of Rupec
		_	1960-61	1961-62	1962-63	1963-64
1.	Grant from Govt. of India		18 ·73	10.06	10.66	10 .40
2.	Other Receipts from Nurseries, Research Stations etc		0 ·69	0 ·42	0 .75	0.90
3.	Deposits and Recoveries of Advances	• •	2 ·18	2 · 20	1 .83	2 .02
	TOTAL		21 60	12 -68	13 -24	13 -32
	Expenditure	_				
1.	Administration		1 -15	1 ·27	1 .27	1 -36
2.	Improvement of Cultivation of Arecanuts	rsi.	16 - 97	7 -00	9 -09	7 -95
3.	Development and Improvement of Arecanut and its products		0.76	0.59	0 .27	0 02
4.	Improvement in Marketing of Arecanuts and its products		0 · 66	0 ·69	0.28	0 -43
5.	Miscellaneous (Payments of Advances recoverable and deposits)		2 · 39	1 -86	1 .88	1 ·78
	Total		21 .93	11 -41	12 · 79	11 .54

Expenditure on measures undertaken for the improvement of cultivation of arecanut, development and improvement of arecanut and its products and their marketing during the year amounted to Rs. 8.40 lakhs which works out to 73% of the total expenditure of the Committee for the year. Out of this Rs. 5.24 lakhs was expended direct by the Committee on its schemes. Rs. 2.88 lakhs was paid as grants-in-aid to 7 State Governments and Rs. 0.28 lakhs to other bodies and institutions engaged in growing, curing, processing, grading, marketing and manufacturing of arecanut and its products.

3. Loss in Seedlings :-

The measures for the improvement of cultivation of arecanut includes distribution of quality seedlings through the Arecanut Research Stations run by the Committee. In the Regional Arecanut Research Station at Mohitnagar which started research activities in 1961-62, heavy damages to seedlings during the period 1961-62 to April, 1963 resulted in a loss of 140065 seedlings valued at Rs. 18,208. It is reported by the Committee in September, 1964, that the loss of seedlings was due to adverse weather conditions, undeveloped nature of land, lack of irrigation facilities and growth of 'Khans' grass.

4. Utilisation of Grants :-

The proper utilisation of grants-in-aid given by the Committee is watched by obtaining (1) audit certificates from the Accountants General in respect of schemes sponsored by State Governments and (2) utilisation certificates in other cases.

At the end of November, 1964, audit and utilisation certificates covering an aggregate amount of Rs. 4:54 lakhs were due in respect of 42 cases of grants-in-aid paid from 1956-57 to 1963-64.

Sd/- T. N. KURIAKOS, Accountant General, Kera 20-1-1965. Kerala.

J. S. UPPAL, Under Secy.

ORDER

New Delhi, the 7th May 1965

No. 13-2/64-Estt.I.—With reference to India, Ministry of Food & Agriculture, (Department of Agriculture) Resolution No. 13-2/64-Estt. I. dated 20th January 1964 setting up an Agricultural Production Board, it has been decided to constitute a Special Committee on Cooperation.

The composition of the Special Committee will be below:

1. Minister, Food & Agriculture

Chairman.

- 2. Minister, Community Development & Cooperation.
- 3. Minister of State in the Ministry of Finance.
- 4. Member of the Planning Commission incharge Cooperation.
- 5. Deputy Governor, Reserve Bank of India.

The Secretary of the Agricultural Production Board will also function as Secretary of the Special Committee.

The Committee may co-opt Ministers, Secretaries or officials of the Government of India or States to attend its meetings as and when necessary.

The main function of the Special Committee will be to deal with concrete problems of purposive co-operative development in a coordinated manner.

The Special Committee will generally meet once a month.

ORDER

ORDERED that a copy of the Order be communicated to all the Ministries and Departments of the Government of India, all the State Governments and Union Territories, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, President's Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, all Members of the Agricultural Production Board Directors of Agriculture and Animal Husbandry in all the States and Union Territories, all Attached and Subordinate Offices under the Ministry of Food & Agriculture (Department of Agriculture).

ORDERED also that the Order be published in the Gazette of India, for general information.

J. C. MATHUR, Jt. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION

New Delhi, the May 1965

No. F.7-36/65.T.1.—Reference Ministry of Education Notification No. F.7-17/64-T.1 dated the 22nd August, 1964 regarding recomposition of the Governing Council of the Indian School of Mines, Dhanbad with effect from the 26th April, 1964. The following change is hereby incorporated at Serial No. 1 under "Chairman", of the Notification referred rto above :

For: "Secretary (Education), Ministry of Education, New Delhi".

Substitute: "Shri G. K. Chandiramani,

Educational Adviser (Technical) and exofficio Additional Secretary,

Ministry of Education, New Delhi".

G. N. VASWANI, Assistant Educational Adviser (Tech.).

MINISTRY OF TRANSPORT

(Transport Wing)

INLAND WATER TRANSPORT RESOLUTION

New Delhi, the 4th May 1965

The Government of India have decided that Shri K. N. Srinivasan, Development Adviser of the Ministry of Transport, shall act as Vice-Chairman of the Ganga-Brahmaputra Water Transport Board, vice Shri C. V. Venkateswaran with effect from 29th June 1964 forenoon till further orders. In this capacity, he shall preside over the meetings of the Board in the absence of the Chairman and attend to the administrative work of the Board.

JASWANT SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 5th May 1965

No. 1(3)/62-Policy.—The following amendment may be carried out in paragraph 2 of this Ministry's Resolution No. 1(3)/62-Policy, dated the 18th May, 1964.

For

Read

4. Shri B. C. Gangopadhyay Deputy Secretary, Ministry of I&P, New Delhi.

Shri A. Das, Deputy Secretary, Ministry of I&P, New Delhi.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated all Ministries/State Governments/Organisations represented in the Committee.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. G. R. IYER, Jt. Secy.

MINISTRY OF WORKS & HOUSING

RESOLUTION

New Delhi, the 5th May 1965

No. 14(30)64-EWI.—The Government of India have decided further to extend to the 31st. May, 1965 the period in which the Study Team on Procedures and Practices in the Central Public Works Department set up vide Resolution No. 14(30)/64-EWI, dated the 17th August, 1964, is expected to submit its report.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all concerned and that it may be published in the Gazette of India for general information.

R. C. MEHRA, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

RESOLUTION

New Delhi, the 26th April 1965

No. WB-12(1)/64.—A Central Wage Board for the heavy chemicals and fertilizers industries was set up by Government of India by their Resolution No. WB-12(1)/64, dated the 3rd April, 1965. The following persons are hereby appointed as members of the Wage Board in addition to the members already mentioned in the aforesaid resolution:—

Members representing Employers

Shri D. M. Trivedi

Nominee of the Indian Chemical Manufacturers' Association, Bombay.

Members representing Workers

Shri V. V. Dravid

Nominee of the Indian National Trade Union Congress.

Shri G. Sundaram Nominee of the All India Trade Union Congress.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information,

B. R. SETH, Dy. Secy.

New Delhi, the 27th April 1965

RESOLUTION

No. WB-21(13)/65.—The Central Wage Board for port and dock workers at major ports, set up by the Government of India by their Resolution No. WB-21(4)/64, dated the 13th November, 1964, has made recommendations, as shown in the appendix, for grant of interim relief.

2. Government have decided to accept the recommenda-tions of the Wage Board and to request the concerned employers to implement the same as early as possible.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. M. MENON, Secy.

APPENDIX

Central Wage Board for Port & Dock Workers at Major Ports The Government of India in the Ministry of Labour and Employment constituted the Central Wage Board for Port and Dock Workers at majort ports by their Resolution No. WB-21(4)/64 dated 13-11-64. By clause (d) of paragraph 3 of the said resolution the Board was asked to submit its recommendations regarding the demand of labour for interim relief within 3 months from the date of the Board starting its work. After hearing the parties, the Board's met for deliberations from 12th to 14th March 1965 but since the Board could not arrive at final conclusion in this meeting and the period of three months was expiring on 14-3-65. and the period of three months was expiring on 14-3-65, the Government, by the Board's Resolution dated 14th March 1964, was requested to extend the period fixed for submission of the Board's recommendations on interim relief by one

The Board again met on 7th, 8th and 9th of April 1965 to consider the question of interim relief and after carefully considering all matters put and pressed before it on this question came to the following conclusions:

- I. The recommendations of the Board, which hereafter follow, should apply to the undermentioned categories of employees connected with the Port and Dock work at major ports, namely:
- A. Employees of major port authorities
 - (1) All categories of employees employed by the authorities of major ports at Bombay, Calcutta, Cochin, Kandla, Madras and Vishakhapatnam covered by the Report of the Committee for Classification and Categorisation for Class III and Class IV employees of major ports and equivalent categories in the port of Murmagoa.
 - (2) Any other categories of manual, clerical, supervisory, etc. employees who hold posts created subsequently or earlier by any of the Major Port Authorities and who are not regarded as Class I and Class II officers.
 - (3) Shore employees of all categories employed Major Port Authorities including A, B, C and other employees directly engaged by the Authorities on daily or other basis. Cand all
- B. Dock workers as defined under dock workers (Regulation of Employment) Act, 1948.
 - (1) Employees covered under the schedules of the Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme relating to the major ports of Bombay, Calcutta, Madras, Cochin and Vishakhapatnam.
 - (2) Employees covered by Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Schemes at the ports of Bombay, Calcutta and Madras.
 - (3) Similar categories of employees as covered under item 1 at the ports of Kandla and Murmagoa.
 - (4) Similar categories of employees covered under item 2 at the ports of Cochin, Vishakhapatnam, Kandla and Murmagoa.
 - (5) Similar categories of employees as in items 1 and 2 at all major ports, whether they are covered by the Schemes or not.
- C. The Employees engaged by the dock labour boards and their administrative bodies
- D. Employees engaged by listed employers
- E. Employees of Employers, other than port authorities, dock labour boards, administrative bodies, Usted employers and registered employers.
 - (1) Ore employees at dumps or depots.

- (2) Employees engaged for handling cargoes in ware-(houses and transit sheds.
- Crew of boats, lighters and barges wholly engaged in the docks and stream whose work is connected with loading and unloading of vessels and other processes of dock and port work.

 (4) Employees engaged in loading and unloading all cargoes (including tea chests) in the dock areas from river crafts, vessels, boats, trucks, etc.
- (5) Employees who come within the definition of "dock workers" under the Dock Workers (Regula-tion of Employment) Act, 1948.
- II. All categories of employees mentioned in clause I, who are getting dearness allowance at the rates applicable to who are getting dearness allowance at the rates applicable to Government employees, should continue to be paid dearness allowance on the pattern of the dearness allowance of the Central Government employees. As and when the Government revises the dearness allowance rates for its employees, these workmen should also be paid dearness allowance at such enhanced rates. This practice should be followed till the final recommendations of the Board come into effect.

(A) If any categories of employees are paid dearness allowance at Government rates, such categories of employees should also be paid dearness allowance from 1st October 1964 at the following rates:—

Pan range	Dearness allowance
Pay range Rs.	Rs.
Below 110	7.50
110 and above but below 150	16.50
150 and above but	10.50
below 210	12.00
210 and upto 300	16.00
301	17.00
302	18.00
303	19.00
304	20,00
305	21.00
306	22.00
307	23,00
308	24,00
309	25.00
310	26,00
311	27.00
312	28.00
313	29.00
314	30.00
315	31.00
316 to 384	31.00
385	31.00
386	32.00
387	33.00
	34.00
388	•
389	35.00
390	36.00
391	37.00
392	38.00
393	39.00
394	40.00
395	41.00
396	42.00
397	43.00
398	44.00
399	45.00
400 to 580	50.00
581	51.00
582	52.00
583	53.00
584	54,00
585	55.00
586	56.00
587	57.00
588	58.0 0
589	59.00
590	60,00
591	61.00
592	62,00
593	63.00
594	64.00
595	65.00
596	66.00
597	67.00
598	68.00
	69.00
599	07.VQ

Provided that :--

- (i) If a different scheme of dearness allowance is applicable to any employees and if under that scheme those employees have received from 31-1-64 an increase in dearness allowance not less than the increases in dearness allowance mentioned in the above rates, no further increase in dearness allowance would be payable to such employees. If it is otherwise, the increase in dearness allowance should be paid from 1-10-64 at rates equal to the difference between the rates in clause (A) above and the increased rates received by them.
- (ii) employee who are being paid consolidated wages or who are piece-rated workers, should be paid a minimum dearness allowance of Rs. 7.50 per month from 1-10-64. However, wage differentials, if any, between higher and lower paid workers in the same channel of promotion should be taken into account for calculating the amount of dearness allowance payable under Clause (A).
- (B) Employees mentioned in provisos (i) and (ii) above should be paid increase in dearness allowance, as and when the Central Government grant increases in the dearness allowance rates applicable to its employees on the same principle as mentioned in proviso (i).
- IV. Besides the payments mentioned above, all categories of employees mentioned in clause I should be paid an interim relief of Rs. 7.80 paise per month with effect from 1st February 1965.

V. In case of daily paid workers, time rated and piece rated, the daily rate of interim relief should be 1/26th or 1/30th of the monthly amount mentioned above, as per present practice. Where there is no such practice, the daily rate of interim relief would be 1/26th of the monthly amount mentioned above, in cases where the worker is not paid any wages for the weekly day of rest.

VI. The interim relief mentioned in clause IV should be shown as a separate item (neither part of basic wage nor part of dearness allowance) till the final recommendations of the Board come into effect. This interim relief should however be considered part of total emoluments in the same manner as enhanced dearness allowance granted by Das Commission.

Sd/- L. P. Dave

Sd/- Bansi Lal

Sd/- D. T. Lakdawala

Sd/- I. B. Das Gupta

Sd/- T. K. Parameswaran Nambiar

Sd/- S. C. Sheth

Sd/- S. R. Kulkarni

Sd/- Makhan Chatterjee

Sd/- Maitreyee Bose

Sd/- N. Ahmed

9th April, 1965.